Regarding the issue of recruitment of Judges, Education Policy and Old Pension Scheme

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे **(**इटावा**) :** महोदय, आरक्षण के जो विरोधी हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ: ?कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, वह भी तुम्हारा है, तुम जो कहो, वह सच है, हम जो कहें, वह झूठ है ।? भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों में जजों की भर्ती आरक्षण व्यवस्था के आधार पर की जाए । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द कर वन नेशन वन एजुकेशन के तहत शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर देश में समान एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाकर लागू किया जाए, जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाए । देश व प्रदेश के कार्मिकों को भविष्य की सुरक्षा के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाल की जाए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** धन्यवाद ।

संसदीय कार्य मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, अब आपका कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है ।

? (व्यवधान) ?*